## पंचायती राज मंत्रालय की पहल:

1. राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन की प्रगति, सामना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों और भावी राह की समीक्षा करने के लिए 4-5 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में केन्द्रीय और राज्य पंचायती राज मंत्रियों, राज्य सचिवों, केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

2. जनजातीय लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की उचित सराहना करते हुए, मंत्रालय ने 2-3 नवंबर, 2018 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर), हैदराबाद में "पीईएसए राज्यों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 10 पेसा राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुडुंबश्री, तिरुवनंतपुरम सहित सात मंत्रालय/संस्थान; एनआरएलएम, ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय रेशम बोर्ड ने भी इसमें भाग लिया। जीपीडीपी के लिए अभिसरण और क्षमता निर्माण पर महत्वपूर्ण अनुशंसाएं सामने आईं; न्यायसंगत विकास के लिए पीआरआई-एसएचजी अभिसरण; पेसा क्षेत्रों में व्यापक जीपीडीपी के लिए जल संसाधन और लघु वन उपज के कृषि विकास और प्रबंधन के लिए योजना।

3. इस मंत्रालय ने अप्रैल, 2016 में पेसा क्षेत्रों के लिए विशेष जीपीडीपी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

———